

वन भूमि अधिकार के संबंध में अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक
दिनांक / / 2019

क्रमांक / २५ / अविडो / रीडर-१ / 2019

भानुप्रतापपुर, दिनांक ०५ / ०२ / 2019

<><><>

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन के तारतम्य में आज दिनांक २८ / ०१ / 2019 को अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित किया गया। अनुभाग समिति के अध्यक्ष सुश्री प्रेमलता मंडावी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों की बैठक हुई। उक्त बैठक में निम्नानुसार माननीय सदस्यगण उपस्थित हुए :-

- 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर
- 2 मंडल संयोजक (आदिम जाति कल्याण विभाग) भानुप्रतापपुर
- 3 श्री रत्नीराम करंगा जनपद सदस्य पंचायत भानुप्रतापपुर
(पुरुष सदस्य अ.ज.जा.)
- 4 श्रीमती बनीता सलाम जनपद सदस्य पंचायत भानुप्रतापपुर
(महिला सदस्य अ.ज.जा.)
- 5 श्री पीलम नरेटी जनपद सदस्य पंचायत दुर्गूकोंदल
(पुरुष सदस्य अ.ज.जा.)

वन विभाग की वन भूमि छोटे-बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि ग्रामों के कब्जाधारियों द्वारा वन भूमि अधिकार पत्र के लिये प्ररतुत दावा आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायतों के समक्ष ग्राम पंचायतों के सचिव, वनरक्षकों एवं वन अधिकार समिति के सदस्यों से स्थल जॉच कराया गया तत्पश्चात् संबंधित ग्रामसभा में व्यक्तिगत के ३२ प्रकरण एवं सामुदायिक दावों के ४१ प्रकरण, कुल १७३ प्रकरण प्राप्त हुए। ग्रामसभा के प्रस्ताव पश्चात् उपरोक्त प्रकरण अनुभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ। अनुभाग स्तरीय समिति में परीक्षण उपरान्त कुल १७३ प्रकरण का रकबा १५२.५५ हे० जिसमें संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत आवेदन पत्रों के संबंध में पदेन सचिव, वनरक्षकों एवं वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया है। तथा वनरक्षकों द्वारा भी मानचित्र तैयार कर संलग्न किये गये हैं।

तदनुसार आवेदन पत्रों उसमें लगे अभिलेखों को अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया गया कुल १७३ प्रकरणों में से ४४ प्रकरण पात्र पाया गया ३१ प्रकरण (व्यक्तिगत एवं सामुदायिक) त्रुटि सुधार हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को वापस किया गया तथा ४१ प्रकरण का रकबा १२.२४ हे० व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य पाया गया।

पूर्व उत्तरी भारत के नवयन पाल एवं उत्तर भारत नियमित के पश्च में स्थीकृत और अपने अधिकार के लिए पूर्ण वार्षिक एवं इनकटक लाइन के लिये कुल कक्ष कमांक २ करोड़ २५८ लैक्टर का पूर्ण के अनुसार द्वितीय वर्ष अधिकार राजीति को द्वितीय अधिकार के प्राप्तियां में अनुप्रादन प्रथावाल अनुविभाग रत्नेश्वर वन अधिकार राजीति के पूर्ण प्रत्युत किया गया। सामिति द्वारा प्राप्त प्रकरण को जीव किया गया। राजीति द्वारा राजीति द्वारा अधिकार द्वितीय दिया गया।

पूर्व में नियम कुल ४६१ प्रकरणों का प्राप्त कनाठिकार राजीति द्वारा पूर्ण जीव का प्राप्त यथा में यही किया गया। प्राप्त यथा द्वारा ५२... प्रकरणों को कनाठिकार यथा पूर्ण पत्र प्रदान करने योग्य पाया तथा कुल प्रकरण ४५३ का नियम किया गया। प्राप्त यथा के अनुप्रादन प्रथावाल अनुविभाग रत्नेश्वर वन अधिकार राजीति के समान प्रत्युत किया गया। सामिति द्वारा प्राप्त प्रकरण की जीव की यह। सामिति द्वारा कुल ५३... प्रकरण रक्वा २१... ६१ अधिकार को वन अधिकार पायता पत्र प्रदान करने योग्य पाया तथा कुल ५३... प्रकरण रक्वा २१... ६१ अधिकार को त्रितीय द्वारा का कारण नियम किया गया।

उपरोक्त प्रकरणों को समेकित कर गिला रत्नेश्वर कनाठिकार राजीति कांकेर की ओर अधिकार विनियमित के लिए अनुशंसा सहित अंग्रेजित किया जाता है।

जीव कर्ता

श्री स्त्रीयम करंगा
सदरम जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर

(Signature)

अनुविभागीय अधिकारी (राजीति)
भानुप्रतापपुर

जीव कर्ता

श्रीमती वनीता रालाम
सदरम जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर

अनुविभागीय अधिकारी (वन) (पूर्व)
भानुप्रतापपुर

१६-३८

श्री पीलम नरेन्द्री
सदरम जनपद पंचायत दुर्गकोदल

(Signature)

मंडल संघोजक
(आदिम जाति कल्याण विभाग)
भानुप्रतापपुर

Annexure-I

**Form I
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)**

No. 229

Date 11.05.2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **2.58** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Shri Bajrang power and ispat Limited, Kanker For Linear Projects In Uttar Bastar Kanker district** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Hahaladdi villages(S) in **Durgukondal** tehsils.

This further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.58** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure B to S.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.


(K.L.Chouhan)
Collector
District Uttar Bastar Kanker (C.G.)